impact
www.impactmeasurement.co.in

Business Standard (Hindi)

Delhi - Feb 08, 2020

Page No: 3
Page Name: Company News
Size: 176 sq. cm
AVE: INR 26,426

Type: Newspaper
Language: Hindi
Circulation: 5,091
Frequency: Daily

News monitored for: Force Motors
Title: Electric buses to pick up speed

इलेक्ट्रिक बसों की रफ्तार होगी तेज

ऋषभ कृष्ण सक्सेना
नई दिल्ली, 7 फरवरी

- **बजट में पूरी तरह तैयार (सीबीयू) वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहन पर आयात शुल्क 25 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया गया है**
- **पुर्जों में आने वाले (सीकेडी) इलेक्ट्रिक वाहन पर शुल्क 10 के बजाय 15 फीसदी करने की घोषणा हुई है**

भारत में इलेक्ट्रिक कार बाजार को लेकर नामी कंपनियां बेशक अभी थोड़ी हिचक रही हैं, लेकिन सार्वजनिक परिवहन के इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियां तेजी से अपने काम में लगी हैं और बजट में ई-वाहन पर आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला उन्हें पसंद आया है। बजट में पूरी तरह तैयार (सीबीयू) वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहन पर आयात शुल्क 25 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया गया है। पुर्जों में आने वाले (सीकेडी) इलेक्ट्रिक वाहन पर शुल्क 10 के बजाय 15 फीसदी करने की घोषणा हुई है।

देश के कई हिस्सों में इलेक्ट्रिक बस चला चुकी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड को यह पहल देसी कंपनियों और 'मेक इन इंडिया' अभियान के लिहाज से एकदम अनुकूल लगती है। कंपनी के कार्यकारी निदेशक एन नागा सत्यम ने कहा के चीनी कंपनियों के हमले से बचने और भारत में ही ई-वाहन की महारत तैयार करने के लिहाज से यह बेहद अहम कदम है। उन्होंने कहा, बाहर से तैयार गाड़ी उतारना आसान काम है, लेकिन उससे देश में तकनीकी कौशल तैयार नहीं होता। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को वाकई रफ्तार देनी है तो ऐसे कदम उठाने ही पड़ेंगे।

ई-बस के विकास में 600 करोड़ रुपये लगाने वाली ग्रीनटेक रोहतांग जैसे दुर्गम इलाके समेत देश भर में 270 से अधिक ई-बस बेच चुकी कंपनी को 2020 में 700 नई ई-बस बेचने की उम्मीद है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार और सूरत प्रशासन समेत कई निगमों से उसकी बात चल रही है। अपने स्थापित वाहन ट्रैवलर का इलेक्ट्रिक संस्करण उतारने वाली पुणे की कंपनी फोर्स मोटर्स भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर कदम बढ़ा रही है और उसे लगता है कि फेम 2 कार्यक्रम के साथ आयात शुल्क बढ़ाना जरूरी था। जर्मन कंपनी से तकनीकी साझेदारी में बना कंपनी का ई-ट्रैवलर बैटरी केअलावा पूरी तरह भारत निर्मित है। कंपनी के प्रबंध निदेशक प्रसन्न फिरोदिया ने कहा कि भारत में ई-वाहन का अनुसंधान एवं विकास (आरऐंडडी) बढ़ाने के लिए सरकार के ऐसे कदम जरूरी हैं क्योंकि विदेश से तैयार गाड़ी लाकर बेचना आसान है मगर निवेश और कौशल के लिहाज से देश को इससे कोई फायदा नहीं होगा।

कंपनी ने करीब 1,000 करोड़ रुपये का निवेश कर शेयर्ड मोबिलिटी का अपना नया प्लेटफॉर्म टी1एन तैयार किया है और इस पर भी ई-ट्रैवलर बनाया जाएगा। फिरोदिया ने बताया कि फीडर वाहनों के तौर पर शहर में इस्तेमाल होने वाले ई-ट्रैवलर के लिए राज्य सरकारों और ओला जैसे फ्लीट ऑपरेटरों से बातचीत की जाएगी।

हालांकि कंपनियों को लगता है कि चार्जिंग ढांचा तैयार करने में सरकार कुछ सुस्त है। फिरोदिया कहते हैं कि लंबी दूरी के वाहन तभी चलेंगे, जब चार्जिंग स्टेशन दिए जाएंगे क्योंकि कंपनियां वाहन बना सकती हैं, चार्जिंग ढांचा नहीं। हालांकि ग्रीनटेक ने अपनी बसों के लिए चार्जिंग डिपो बनाए हैं, जहां से पूरी तरह चार्ज होने के बाद ही बस किसी शहर के लिए रवाना होती है।

© Business Standard (Hindi) http://hindi.business-standard